

रोमन कैथोलिक मिशन

बनाम

मद्रास राज्य और अन्य

जनवरी 14, 1966

[पी.बी. गर्जेन्द्रगडकर, सी.जे. के.एन. वांचू,

एम. हिदायतुल्ला, वी. रामास्वामी और पी. सत्यनारायणराजू, जेजे.]

मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1927 का 2, धारा 44 बी-
वाल्ड डाईटी

मेलवारम-सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण- सीमा की अवधि।

इनाम फेयर रजिस्टर-का मूल्य

मुकदमे की ज़मीनें देवस्थानम को पूजा करने के लिए इनाम के रूप में दी गई थी। चूँकि उन्हें राजस्व से अलग कर दिया गया था, राजस्व मण्डल अधिकारी ने धारा 44 बी मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1926 के अन्तर्गत यह मानते हुए कि इनाम में मेलवारम और कुडिवरम दोनों शामिल थे, उन्हें फिर से शुरू किया गया और उन्हें पुनः देवस्थानम को प्रदान किया गया। अपीलार्थी मिशन, जो विदेशी के रूप में भूमि में काबिज था, ने एक घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि इनाम में

केवल मेलवरम शामिल था, कि अनुदान एक व्यक्तिगत इनाम था जो धारा 44 बी के तहत फिर से शुरू करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। और यह कि यह धारा अपने आप में प्रांतीय विधानमंडल के विपरीत थी। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इनाम में दोनों वाराम शामिल थे, लेकिन यह धारा 42 बी के दायरे से बाहर एक व्यक्तिगत इनाम था, और इसलिए मिशन के पक्ष में निर्णय लिया। अपील पर उच्च न्यायालय ने दोनों निष्कर्षों को उलट दिया और माना कि यह धारा अधिकार के भीतर थी।

मिशन और देवस्थानम द्वारा इस न्यायालय में की गई अपीलों में,

अभिनिर्धारित: (i) भारत सरकार अधिनियम, 1915 के तहत प्रांतीय विधानमंडल की कई शक्तियों के एकीकरण ने धार्मिक और धर्मार्थ दान से जुड़े इनामों के विषय पर व्यापक चरण विभाजन के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की। भले ही कोई संदेह था, गवर्नर-जनरल इन काउंसिल को नियम 4 भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत हस्तांतरण नियमों के अन्तर्गत प्रश्न का निर्णय कर इस मामले पर किसी भी विवाद को समाप्त करना चाहिए। इस धारा और 1946 में इसमें किए गए संशोधन को धारा 292 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्तर्गत कायम रखा गया और उसके तहत प्रांतीय विधानमंडल की शक्ति धारा 44 बी के तहत पूरी तरह से प्रांतीय विधानमंडल की क्षमता के भीतर थी और यही बात संबंधित धाराओं

35 मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 तथा संविधान के बारे में भी सच होगी। [297 सी-ई, एच]

(ii) इनाम फेयर रजिस्टर में एक आधिकारिक घोषणा शामिल की गई जो विस्तृत पूछताछ का परिणाम थी। इस संबंध में एकत्र किए गए सभी साक्ष्य को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने या घोषित होने से पहले प्रत्येक इनाम के सन्दर्भ में सावधानीपूर्वक छान-बीन और विचार किया गया था। सकारात्मक और उचित साक्ष्य के अभाव में, ऐसी घोषणा का सर्वोच्च महत्व होना चाहिए। उच्च न्यायालय, स्वीकार्य साक्ष्य पर, सही निष्कर्ष पर पहुँचा कि केवल मेलवरम ही इनाम का विषय था और इनाम को हमेशा देवस्थानम की अर्चक सेवा के लिए पारिश्रमिक माना जाता था। निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि यह एक व्यक्तिगत इनाम था, गलत था। [290 बी; 294 डी-ई; 295 ई, एफ]

अरुणाचलम चेट्टी और अन्य वी. वेंकटचलपति, एल आरण 56 आई एण 204, लागु ।

(ii) बीमारुद्ध 32 और 33 विक्ट. सी. 29 केवल इनाम आयोग द्वारा दिए गए स्वामित्व विलेखों को मान्य किया। इसने कोई अनुबंध नहीं बनाया, और इसलिए कोई अन्य अनुदान जो इसकी शर्तों के उल्लंघन पर फिर से देय है, यह इनाम इसके नियमों और शर्तों के अनुसार फिर से देय था। विमुख्ता पर, यह धारा 44 बी के तहत पुनर्ग्रहण होने के लिए

उत्तरदायी था। और चूंकि सरकार द्वारा केवल मेलवारम का पुनर्ग्रहण किया जाना था, और चूंकि किसी भी कानून द्वारा सीमा की अवधि निर्धारित नहीं है, इसलिए मीशन द्वारा प्रतिकूल कब्जे का कोई सवाल ही नहीं है। [298 ई एफ]

बोड्डापल्ली जगन्नाथम बनाम राज्य सचिव, आई. एल.आर.27 मैड। 16 और सुब्रमण्यम चेट्टियार बनाम राज्य सचिव 28 एमण् एलण् जेण् 392 लागु।

(iv) पुनः आरम्भ और पुनर्ग्रहण देने से जो किया गया वह केवल देवस्थानम को वह वापस करने के लिए था जो उसने खो दिया था। इसलिए यह एक सांप्रदायिक धार्मिक संस्था को लाभ में डालने का मामला नहीं था। [297 एफ.जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 389/1964 और 69/1965।

क्रमशः एस संख्या 773 और 787 और 1954 की अपील संख्या 734 में मद्रास उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर 1959 के फैसले और आदेशों के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता (सीए संख्या 389/64 में) प्रतिवादी संख्या 1 (सीए संख्या 69/65 में) के लिए एसजी रामचंद्र लायर, जेबी दादाचंजी, ओसी माथुर और रविंदर नारायण।

रंगनाथम चेट्टी और एवी रंगम, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए (सीए संख्या 389/64 में)

एवी विश्वनाथ शास्त्री के लिए, और आर गोपालकृष्णन, प्रतिवादी संख्या 2 (सीए संख्या 389/64 में) और अपीलकर्ता (सीए संख्या 69/65 में) के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

हिदायतुल्ला, जे. द्वारा सुनाया गया था, मदुरै तालुक के वंडियूर गांव में दो ब्लॉक हैं, जिनके नाम मेलाप्पप्पथु और कीलाप्पाथु हैं। प्रथम ब्लॉक 28.90 एकड़ है और सर्वेक्षण क्रमांक 45 है (पुराना सर्वेक्षण क्रमांक 33 था और क्षेत्रफल 28.75 एकड़ है)। कनियास में क्षेत्रफल का विस्तार 21-9 है। दूसरा ब्लॉक सर्वे नंबर 78, क्षेत्रफल 20.88 एकड़ (पुराना सर्वे नंबर 100 और क्षेत्रफल 20.53 एकड़) है। कनीज़ में क्षेत्रफल का विस्तार 17-10 है। ये ज़मीनें मूल रूप से मनागिरी गांव में स्थित थीं, और ये ज़मीनें मान्यम ज़मीनें थीं, यानी कम मूल्यांकन पर या सेवाओं के विचार के लिए पूरी तरह से मुफ्त रखी गई ज़मीनें थीं। यह अब रिकॉर्ड से स्पष्ट है और वास्तव

में यह सभी हाथों से स्वीकार किया गया है कि वे प्राचीन काल में शासकों द्वारा दिए गए इनाम का विषय थे और उन्हें श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर देवस्थानम, मदुरै में पूजा के लिए रखा गया था। 1948 में राजस्व मंडल अधिकारी, मदुरै ने जांच के बाद माना कि इनाम में मेलवाराम और कुडीवरम दोनों शामिल थे और चूंकि इनाम की भूमि अलग कर दी गई थी, इसलिए इनाम को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। उनका आदेश 9 अप्रैल, 1948 को पारित किया गया था और कथित तौर पर धारा 44बी मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1926 (1927 का मद्रास अधिनियम 2) के तहत था। इनाम की ज़मीनें फिर से शुरू कर दी गईं और देवस्थानम को वापस दे दी गईं। उस समय भूमि सेंट मैरी चर्च, मदुरै के रोमन कैथोलिक मिशन के कब्जे में थी, और अक्टूबर, 1894 से मिशन के पास थी। राजस्व मंडल अधिकारी के आदेश के खिलाफ मिशन ने जिला कलेक्टर के पास अपील की। अधिनियम की धारा 44-बी (4) के अन्तर्गत अपील 13 मार्च 1949 को खारिज कर दी गई। जिला कलेक्टर ने यह भी माना कि इनाम में दोनों वारम शामिल थे।

इसके बाद रोमन कैथोलिक मिशन ने धारा 44-बी(2)(डी) के तहत अधीनस्थ न्यायाधीश, मदुरै की अदालत में एक मुकदमा इस घोषणा के लिए दायर किया कि इनाम में केवल मेलवाराम शामिल है। मुकदमा बाद में जिला न्यायाधीश द्वारा अपनी फाइल में वापस ले लिया गया और इसे

1954 के ओ.एस. 1 के रूप में पंजीकृत किया गया। मिशन ने अधीनस्थ न्यायाधीश मदुरै के न्यायालय में एक और मुकदमा भी दायर किया, जिसे भी जिला न्यायाधीश ने अपनी फ़ाइल में वापस ले लिया और उसे 1954 के O. S. 2 के रूप में पंजीकृत किया । दूसरा मुकदमा मात्र सामान्य था। इसने घोषणा की भी मांग की जो 1954 के ओएस 1 का विषय था और इसने भूमि को फिर से शुरू करने के अधिकार के साथ-साथ राजस्व अदालतों द्वारा फिर से शुरू करने के दिए गए आदेश के अधिकार पर भी सवाल उठाया। उस मुकदमे में मिशन ने तर्क दिया कि विशेष इनाम 1927 के मद्रास अधिनियम 2 की धारा 44बी के दायरे से बाहर था, उक्त इनाम एक व्यक्तिगत इनाम था और उस धारा के तहत बहाली के लिए उत्तरदायी नहीं था और यह धारा स्वयं प्रांतीय विधानमंडल के अधिकाराधीन थी। मद्रास प्रांत (अब मद्रास राज्य) और श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरल देवस्थानम, मदुरै को प्रतिवादी बनाया गया।

जिला न्यायाधीश ने 1954 के ओएस नंबर 1 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इनाम में दोनों वारम शामिल थे। 1954 के ओएस 2 में भी वही निष्कर्ष दोहराया गया और आगे यह माना गया कि बहाली का आदेश अमान्य और क्षेत्राधिकार के बिना था क्योंकि विचाराधीन इनाम व्यक्तिगत इनाम थे और धारा 44बी के दायरे में नहीं आते थे। जिला न्यायाधीश ने इस आशय की घोषणा की और देवस्थानम के खिलाफ

निषेधाज्ञा भी जारी की, जिसने तब तक भूमि पर कब्जा नहीं किया था। 1954 के ओ.एस.1 में निर्णय के विरुद्ध मिशन ने अपील की और 1954 के ओ.एस.2 में निर्णय के विरुद्ध देवस्थानम् और मद्रास राज्य ने अपील दायर की। 1954 का ए.एस. 734, रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा ओ.एस. 1954 के निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया था। 1954 के ए.एस. 773 और 787, मद्रास राज्य और श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरल आदि क्रमशः देवस्थानम् द्वारा 1954 के ओ.एस. 2 में दायर किए गए थे। उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर, 1959 को तीनों अपीलों पर फैसला सुनाया और 1954 के ए.एस. 734 में एक अलग निर्णय सुनाया और अन्य दो अपीलों का एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया।

यह निष्कर्ष कि दोनों वारम इनाम के विषय थे, उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था और 1954 के ओ.एस. 1 का फैसला डिक्री किया था। यह निष्कर्ष कि इनाम व्यक्तिगत थे और इसलिए पुनर्गठन नहीं किये जा सकते को उलट दिया गया और 1954 के ओ.एस. 2 को इस संशोधन को छोड़कर खारिज करने का आदेश दिया गया कि इनाम को केवल मेल्वारम का माना गया था, जो कि अन्य मुकदमे में एकमात्र निर्णय था। उच्च न्यायालय ने धारा 44-बी की अधिकारातीत प्रकृति के बारे में सभी विवादों को खारिज कर दिया । उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों को इस न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित किया है और यह अपील और 1965

की सिविल अपील 69 (श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरल, आदि देवस्थानम, इसके कार्यकारी अधिकारी बनाम रोमन कैथोलिक मिशन और दो अन्य) के माध्यम से दायर की गई है। यह अपील 1954 के ओएस 2 से संबंधित है और रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा मद्रास राज्य और देवस्थानम को प्रतिवादी बनाकर दायर की गई है। सहयोगी अपील देवस्थानम द्वारा है और उत्तर देने वाला रोमन कैथोलिक मिशन है। इस फैसले से दोनों अपीलों का निपटारा किया जाएगा।

इससे पहले कि हम इस अपील में विवादग्रस्त मामलों का उल्लेख करें, हम उन हस्तांतरणों की एक रूपरेखा देंगे जिनके द्वारा रोमन कैथोलिक मिशन को भूमि पर कब्जा प्राप्त हुआ। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी भी समय इस पर गंभीरता से सवाल उठाया गया है कि ये ज़मीनें मूल रूप से मालिक के रूप में कुछ मुसलमानों की थीं। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है, (जैसा कि हम वर्तमान में देखेंगे) कि भूमि स्वयं किसी अनुदान के अधीन नहीं थी, बल्कि थेर्वा, यानी, पैसे में भुगतान किया गया किराया, अकेले अनुदान का विषय था। यद्यपि थेरवा में रियायत के संबंध में अधिकार भट्टारों के नाम पर जारी किया गया था जो देवस्थानम के अर्चक थे, रियायत और भूमि दोनों ही अलगाव के अधीन थे। 12 मई, 1861 से पहले भी मेलाप्पापथु का आधा हिस्सा अंदिअप्पा चेट्टियार के बेटे कृष्णास्वामी चेट्टियार ने खरीदा था, और दूसरा आधा हिस्सा उन्होंने

1 मई, 1861 को खरीदा था। इसी तरह, कृष्णास्वामी चेट्टियार ने मूल मालिकों से कीलप्पापथु का आधा हिस्सा खरीदा था। 4 जनवरी, 1863 को मेलप्पापथु में आधा हिस्सा कृष्णास्वामी:चेट्टियार से चोकलिंगम पिल्लई द्वारा खरीदा गया था। उन्होंने मुथुरामलिंगम पिल्लई के लाभ के लिए, कीलप्पापथु के कृष्णास्वामी चेट्टियार के हिस्से का आधा हिस्सा भी खरीदा। अक्टूबर 1864 में चोकलिंगम ने मुथुरामलीमगम के पक्ष में औपचारिक रिहाई की अनुमति दे दी। कीलाप्पप्पाथु का दूसरा आधा हिस्सा, जो मूल मालिकों के पास जारी रहा, उन्होंने 18 जुलाई, 1867 को कृष्णास्वामी चेट्टियार (एक कानी से कम) को बेच दिया। 25 जून, 1870 को मुथुरामलिंगम पिल्लई ने अपने हिस्से में जारी भूमि के एक हिस्से का सूदखोर बंधक बना कर मुथुरामलिंगम पिल्लई के पुत्र वैरावलिंगम पिल्लई के पक्ष में निष्पादीत किया। यह स्पष्ट नहीं है कि वह उनका अपना बेटा था या नहीं, लेकिन पूछताछ करना प्रासंगिक नहीं है। 14 दिसंबर, 1871 को मुथुरामलिंगम की विधवा, अडाइकलथम्मल ने, अपने नाबालिग बेटे मुथुस्वामी पिल्लई की ओर से, मेलप्पापथु का आधा हिस्सा और कीलाप्पप्पाथु का चौथाई हिस्सा कृष्णास्वामी चेट्टियार को बेच दिया। 25 जून, 1870 के बंधक का भुगतान कर दिया गया और कृष्णास्वामी ने 11 सितंबर, 1872 को संपत्ति छुड़ा ली। इससे कृष्णास्वामी चेट्टियार के स्वामित्व से एक कानी भूमि छूट गई, जो मूल मालिकों के पास अभी भी थी। 17 जून, 1872 को, कृष्णास्वामी चेट्टियार ने वह ज़मीन खरीदी और

इस तरह वह इन दोनों अपीलों में शामिल सभी ज़मीनों के मालिक बन गए। कृष्णास्वामी ने सभी जमीनों को एंडियप्पा चेट्टियार के पक्ष में एक रिहाई और बिक्री विलेख निष्पादित किया और ऐसा प्रतीत होता है कि एंडियप्पा चेट्टियार खरीद के लाभार्थी थे और इस प्रकार वास्तविक मालिक थे।

20 अक्टूबर, 1894 को रोमन कैथोलिक मिशन ने 1,500 रुपये और 6,500 रुपये में मालापपाथु का बड़ा हिस्सा खरीदा। इस ब्लॉक का शेष भाग और कीलाप्पपाथु ब्लॉक एक एंथोनिमुथु द्वारा खरीदा गया था और जब उसने अपना स्वयं का शीर्षक स्थापित किया तो मिशन ने उस पर मुकदमा दायर किया और उप-न्यायालय, मदुरै पश्चिम से 1895 के ओएस 45 में एक डिक्री प्राप्त की। इस प्रकार पिछली सदी से दोनों ब्लॉकों पर रोमन कैथोलिक मिशन का कब्ज़ा रहा है। अब हम दोनों अपीलों के तर्कों पर विचार करेंगे।

इस मामले के दो पहलुओं पर हाई कोर्ट और जिला जज में मतभेद है। दोनों पहलू विवाद में इनाम की प्रकृति से जुड़े हुए हैं। पहला यह है कि क्या इनाम अकेले मेलवाराम का था या इसमें दोनों वारम शामिल थे और दूसरा यह कि क्या इनाम एक व्यक्तिगत इनाम था जिसे फिर से शुरू नहीं किया जा सकता था या मंदिर की सेवा के लिए दिया गया था, जिसे तब फिर से शुरू किया जा सकता था जब कोई अलगाव और सेवा बंद कर दी

गई। धारा 44 बी मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1926 की वैधता के प्रश्न पर, जिला न्यायाधीश ने इनाम की प्रकृति पर अपने निर्णय के मद्देनजर कोई भी राय व्यक्त करना अनावश्यक पाया, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत माना और फिर से शुरू करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर विचार किया, प्रश्न किया और प्रावधान को वैध माना। इन अपीलों में रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा स्थापित प्रतिकूल कब्जे के दावे के साथ-साथ इन तीन बिंदुओं पर मुख्य रूप से तर्क दिया गया था। हम इनाम की प्रकृति पर विचार करके शुरू करेंगे - पहले इस दृष्टिकोण से, कि क्या इसमें दोनों वारम शामिल थे और फिर इस दृष्टिकोण से कि क्या यह मंदिर के लिए अनुदान था या किसी कार्यालय के लिए अनुदान था जिसका पारिश्रमिक भूमि का उपयोग या सेवा के बोझ से दबी भूमि का अनुदान द्वारा दिया जाना था। हम आगे उन तर्कों पर विचार करेंगे जिनके आधार पर धारा 44 बी को अधिकारातीत और शून्य कहा गया है। अंत में, हम प्रतिकूल कब्जे के प्रश्न पर विचार करेंगे।

चूँकि इनाम देने और उसकी शर्तों को दर्ज करने वाला कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए किसी को कई दस्तावेजों की ओर रुख करना होगा, जिनसे उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने इनाम में क्या शामिल किया गया था, इसके बारे में विपरीत निष्कर्ष निकाले हैं। निःसंदेह, इसमें कोई विवाद नहीं है कि इनाम में कम से कम मेलवाराम शामिल रहा होगा। किसी भी

घटना में ऐसा अवश्य हुआ होगा। इस प्रकार एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या इसमें कुडीवरम भी शामिल है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि दोनों वारम शामिल थे, जिला न्यायाधीश ने मदुरै के अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के 1944 के एक पुराने मामले ओएस नंबर 124 के रिकॉर्ड से कुछ पट्टों की प्रमाणित प्रतियों पर विचार किया। ये दस्तावेज़ प्रदर्श बी-4, 5, 6 और ए- 68, 69 और 77 हैं। प्रदर्श बी-4 फसली वर्ष 1348 और 1349 के लिए निष्पादित एक करालनामा (समझौता) है जिसके द्वारा पट्टेदारों ने उपज का 1/3 हिस्सा मेलवाराम के रूप में सोंपने और कीलप्पापथु से पट्टे पर ली गई भूमि से कुदिवारम के रूप में 2/3 हिस्सा बनाए रखने का वचन दिया। प्रदर्श बी-5 संपूर्ण कीलप्पापथु नन्जा (गीली) भूमि पर खेती करने के लिए एक और पट्टा है। प्रदर्श बी-6 कीलप्पापथु में नन्जा भूमि के संबंध में एक मुचिलिका है जिसके द्वारा पट्टेदार ने आधी उपज का भुगतान मेल्वारम के रूप में और शेष आधे को कुडीवरम के रूप में अपने पास रखने का वचन दिया। ये दस्तावेज़ निस्संदेह मामले पर प्रकाश डालते लेकिन ये स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि ये केवल प्रतियां थीं। मूल प्रतियाँ किसी भी समय प्रस्तुत नहीं की गईं और न ही द्वितीयक साक्ष्य देने के अधिकार की स्थापना के लिए कोई नींव रखी गई। उच्च न्यायालय ने उन्हें खारिज कर दिया और ऐसा निर्णय लेना स्पष्ट रूप से सही था। यदि हम इन दस्तावेज़ों को विचार से बाहर कर दें, तो अन्य दस्तावेज़ यह नहीं दिखाते हैं कि इनाम में कुदिवारम भी शामिल था। प्रदर्श ए-3 इनामों से

संबंधित मांडकुलम तालुक के मानागिरी गांव के ग्रामीण विवरण से लिया गया उद्धरण है। यह सन् 1802-1803 के लिए है। भूमि को क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त भूमि के साथ पर्याप्त रूप से पहचाना जाता है। भूमि को मीनाक्षी सुंदरश्वरल मंदिर के लिए संचालित स्टेलाथेर इनाम पोरुप्पा मान्यम के रूप में वर्णित किया गया था। 5 वी रिपोर्ट पृष्ठ 765 के अनुसार पोरुप्पु कम या छोड़ दिया गया किराया है, से हमें संकेत मिलता है कि इनाम में क्या शामिल था। खाते से पता चलता है कि 96 पॉस 0 फैनोम्स और 15 थुड्डू के कुल मूल्यांकन से, पोरुप्पु केवल 19 पॉस 2 फैनोम्स और '3 थुड्डू था। फिर से प्रदर्श ए-5, जो 1217 फसली यानी पांच साल बाद के मणिगिरि गांव के इनाम खाते का उद्धरण है, शीर्षक था इनाम पूछताछ मौजे (गांव) मणिगिरि"। अब, मौजे शब्द का उपयोग उन गांवों के संबंध में किया जाता है जिनमें कृषक खेती योग्य भूमि के मालिक हैं। यह लंबे समय से ऐसा ही माना जाता रहा है [देखें वेंकट सस्त्रुलु बनाम सीतारामाडु,¹ प्रति सदाशिव लायर, जे. और सेथय्या बनाम सोमयाजुलु² टिप्पणी कॉलम में पोरुप्पु राशि देय कहा गया है और यह लगभग पहले उल्लेखित पोरुप्पु से मेल खाता है, और मंदिर की सेवा का एक और उल्लेख है। पट्टों में 1856, 1857 और 1860 के वर्षों के ए-6 से ए-8 प्रदर्शित हैं, साथ ही सौरनदायम मनिबम पोरुप्पु का भी वर्णन है जो कि रियायत पर धन के रूप में देय राजस्व है।

1- आईएलआर 38 मैड. 891.

2- आईएलके 52 मैड।453,463. (पीसी)

इनामदारों ने खुद इनाम पूछताछ में मेल्वरम अधिकारों और प्रदर्श ए-10 और ए-1 1 से अधिक कुछ भी दावा नहीं किया, जो इनाम विवरण (1862) हैं और इनाम मेला रजिस्टर दिनांक 25 सितंबर, 1863 स्टालथार पोरुप्पु मणिबम का फिर से उल्लेख किया गया है और इनाम को मंदिर के स्थानिक के रूप में भट्टरों के नाम पर पंजीकृत किया गया था।

एकमात्र दस्तावेज जिसमें विपरीत टिप्पणी की गई थी वह ओथी-डीड (बंधक) पूर्व था, जो 1876 का प्रदर्श ए-64 है, जिसके द्वारा मुथु मीनाक्षी ने कृष्णास्वामी चेट्टियार के पक्ष में 20 वर्षों के लिए इनाम के आधे हिस्से में अपना मेलवाराम हित गिरवी रख दिया। मुथु मीनाक्षीअम्मल देवस्थानम के स्थानिकम विक्रमपांडिया बत्तर की पत्नी थीं। इसका संबंध मेलप्पापाथु और कीलाप्पप्पाथु दोनों से था और मोरागागी ने पोरुप्पु का भुगतान करने का वचन दिया। संपत्ति का वर्णन करते समय यह कहा गया था कि मेल्वरम और कुडीवरम अधिकार गिरवीदार के कब्जे में थे। यह संभवतः मामलों की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि, कृष्णास्वामी चेट्टियार पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे जमीन के साथ-साथ इनाम भी हासिल कर रहे थे। इसी तरह का एक बयान कृष्णास्वामी चेट्टियार ने प्रदर्श ए-42 में दिया था, लेकिन यह मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। यह स्पष्ट है कि कृष्णास्वामी चेट्टियार ने न केवल मेलवारम बल्कि कुडीकरम भी पहले ही हासिल कर लिया था। किसी भी दस्तावेज ने

वास्तव में यह नहीं दिखाया कि इनाम में कुडीवरम भी शामिल था। इनाम में कुदिवारम को शामिल करने का कोई अन्य सबूत नहीं है और लेन-देन मेल्वरम के साथ था - जिसका दावा अकेले इनामदारों ने इनाम पूछताछ में किया था।

हालाँकि इस मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक चर्चा की गई है, हमने सामग्री की फिर से जाँच की है और यहाँ निर्धारित किया है, जिससे हम यह मानने के लिए पर्याप्त कारण मानते हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कुडीवरम इनाम का विषय था। सभी स्वीकार्य मामले इस निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि केवल मेलवाराम ही अनुदान का विषय था। 1965 की सिविल अपील संख्या 69 में अपीलकर्ता ने हमें दो निर्णयों से अवगत कराया और ट्रायल जज के दृष्टिकोण पर हम पर दबाव डाला। हमने दो विचारों पर विचार किया है और हमारी राय है कि उच्च न्यायालय रिकॉर्ड पर स्वीकार्य साक्ष्य पर सही निष्कर्ष पर पहुंचा है। इस प्रकार 1965 की सिविल अपील संख्या 69 विफल होनी चाहिए और हमारे द्वारा यह निष्कर्ष अन्य अपील में भी पढ़ा जाएगा।

अब हम इस पर विचार करेंगे कि क्या इनाम व्यक्तिगत इनाम था, या देवस्थानम की सेवा के लिए था। उच्च न्यायालय ने रासा कौंडन बनाम जानकी अम्मल³ मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा

3- [1950] 2 एमएलजे 177

किया है। इनाम विभिन्न प्रकार के होते हैं। उन्हें भू-राजस्व में रियायत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात्, क्या संपूर्ण भू-राजस्व माफ कर दिया गया है या कुछ हिस्सा, या क्या भूमि पैसे के भुगतान के अधीन रखी गई है। जहां संपूर्ण भू-राजस्व का भुगतान किया जाता है, वहां इनाम को सर्व इनाम, सर्व मान्यम, सर्व डंबला या दारोबस्ट इनाम जैसे नामों से जाना जाता है। जब मिट्टी पर अधिकार को इनाम में शामिल नहीं किया जाता है तो इसे उस हिस्से के अनुसार जाना जाता है जो मुफ्त था जैसे अर्ध मन्यम (आधा), चतुर्भागम (1/4) आदि। तीसरे प्रकार के इनाम में छोड़े गए लगान का भुगतान शामिल होता है जिसे कहा जाता है पोरुप्पु, सवाल ये है कि क्या ये इनाम जिसमें सिर्फ एक पोरुप्पु था-देय में मिट्टी का अधिकार शामिल है। वेंकट बनाम सीतामदु⁴ में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि कानून में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि इनाम अनुदान, भले ही ब्राह्मण को दिया गया हो, उसमें कुदिवारम शामिल नहीं है। हमने इस अवलोकन को ध्यान में रखा है लेकिन हमारा मानना है, कि इस मामले में सबूत इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि इनाम में केवल मेल्वारम शामिल था। इस प्रकार यह एक इनाम था जहां भूमि को छोड़े गए किराए के रूप में एक राशि के भुगतान के अधीन रखा गया था। यह अर्चकों को प्रदान किया गया था और उनके नाम पर दर्ज किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने जमीनें अपने कब्जे से अलग की और सवाल यह

4- आईएलआर 38 मैड. 891.

है कि क्या इनाम को फिर से शुरू किया जा सकता है या नहीं। धारा 44-बी मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती (संशोधन) अधिनियम 1934 (1934 का मद्रास अधिनियम XI) 1927 के मूल अधिनियम II में डाली गई और संशोधन द्वारा आगे संशोधित कर 1946 के अधिनियम X में लिखा है।

"44-बी. (1): मठ या मंदिर के समर्थन या रखरखाव के लिए दिए गए किसी भी इनाम के पूरे या किसी हिस्से का कोई भी विनिमय, उपहार, बिक्री या बंधक, और पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई पट्टा या ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई, पुष्टि की गई या मान्यता प्राप्त किसी दान या उससे जुड़ी सेवा का प्रदर्शन शून्य और अमान्य होगा।

स्पष्टीकरण-

(2)(ए) कलेक्टर, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, या मठ या मंदिर के ट्रस्टी या सहायक आयुक्त या बोर्ड के या मठ या मंदिर में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसे ट्रस्टी, सहायक आयुक्त या बोर्ड की सहमति प्राप्त की हो, आदेश द्वारा, निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर, ऐसे किसी भी इनाम के पूरे या किसी हिस्से को फिर से शुरू कर सकता है, अर्थात्:-

(i) ऐसे इनाम या हिस्से के धारक ने उसे या उसके किसी हिस्से का विनिमय, उपहार, बिक्री या बंधक बनाया है या पांच साल से अधिक की अवधि के लिए उसे या उसके किसी हिस्से का पट्टा दिया है, या

(ii) ऐसे इनाम या भाग का धारक ऐसे मठ या मंदिर के रीति-रिवाज या उपयोग के अनुसार दान या सेवा करने या प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में विफल रहा है, जिसके लिए इनाम बनाया गया था, जिसे ब्रिटिश सरकार या उक्त दान या सेवा के किसी भाग द्वारा पुष्टि या मान्यता प्राप्त है, जैसा भी मामला हो या

(iii) कि मठ या मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो गया है या विचाराधीन दान या प्रश्नगत सेवा का निष्पादन किसी भी तरह से असंभव हो गया है।

इस खंड के तहत आदेश पारित करते समय, कलेक्टर यह निर्धारित करेगा कि क्या ऐसा इनाम या इनाम जिसमें ऐसा हिस्सा शामिल है, जैसा भी मामला हो, मेल्वरम और कुडिवारम दोनों का अनुदान है या केवल मेल्वरम का।

(एफ) जहां इस धारा के तहत किसी इनाम या इनाम के हिस्से को फिर से शुरू किया जाता है, कलेक्टर या जिला कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा, ऐसे इनाम या हिस्से को फिर से प्रदान करेगा-

(I) मठ या मंदिर संघ के लिए बंदोबस्ती के रूप में-

धारा 44 बी की उप-धारा (1) पीबी भीमसेना राव बनाम सिरिगिरि पघेल्ला रेड्डी और अन्य में व्याख्या का विषय था⁵। तब सवाल यह था कि क्या धारा 44-बी(1) में सेवा के बोझ से दबी भूमि के अनुदान को शामिल किया गया है, जबकि एक कार्यालय के लिए अनुदान को भूमि के उपयोग से पारिश्रमिक दिया जाता है, लेकिन जब सेवा निष्पादित नहीं की जाती है, तो इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। इनाम अनुदान के इन दो अलग-अलग पहलुओं से निपटने में, गर्जेन्द्रगडकर जे. (जैसा कि वह तब थे) और वांचू जे. बताते हैं कि पूर्व एक सेवा का मामला नहीं है, उचित अनुदान है और ऐसा अनुदान केवल तभी फिर से शुरू किया जा सकता है यदि सेवा पूरी न होने पर अनुदान की शर्तें फिर से शुरू करने पर विचार करती हैं। दूसरा एक उचित सेवा इनाम है और जब तक सेवा नहीं की जाती तब तक बहाली अपरिहार्य है। वे यह भी बताते हैं कि धारा 44-बी के अधिनियमन से पहले इनामों को बोर्ड के स्थायी आदेशों द्वारा शासित किया जाता था: नियम 54 इसने राजस्व अधिकारियों पर यह देखने का कर्तव्य रखा कि इनाम आयुक्त द्वारा किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्थान की सेवा के लिए पुष्टि किए गए इनामों का उपयोग सेवा के प्रदर्शन के बिना नहीं किया गया है। अनुदान तब फिर से शुरू किया जा सकता था जब दी गई भूमि का पूरा हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा हस्तांतरित हो गया हो या खो गया हो। हालाँकि, ऐसे मामलों से दो तरह से निपटने का प्रावधान किया गया था।

5- [1962] 1 एससीआर 339

या तो फिर से शुरू किया गया था या अनुदान प्राप्तकर्ता को कब्जे में छोड़ दिया गया था और पूरा मूल्यांकन उस पर लगाया गया था, अंतर उस विशेष दान या संस्थान को उपलब्ध कराया गया था जिसकी सेवा के लिए अनुदान दिया गया था। इसलिए, सेवा के बोझ तले दबे व्यक्तिगत इनामों के मामले में, जब सेवा नहीं की जा रही थी, चाहे कोई अलगाव था या नहीं, पूर्ण मूल्यांकन की मांग की जा रही थी, व्यक्तिगत भाग अनुदान प्राप्तकर्ता पर छोड़ दिया गया था लेकिन रियायती भाग संबंधित दानी संस्था को दिया गया था।

धारा 44-बी के अधिनियमन के बाद बोर्ड के स्थायी आदेश नियम, 54 में संशोधन किया गया और धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इनामों को वर्गीकृत किया गया:

(i) किसी हिंदू मठ या मंदिर से जुड़े दान या सेवा के प्रदर्शन के लिए दिए गए इनाम; और

(ii) इनाम वर्ग (i) के अंतर्गत नहीं आते।

पहले दो प्रकार मद्रास के हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित थे और दूसरे बोर्ड के स्थायी आदेश नियम 54 द्वारा शासित थे। इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए यह बताया गया है कि धारा 44-बी(1), अपनी भाषा की चौड़ाई के बावजूद, "केवल एक प्रतिबंधित

व्याख्या के लिए खुला है और इसमें उन इनाम को शामिल किया गया है जिनमें पूरी आय या बहुत बड़ा हिस्सा सेवा के लिए आवश्यक है और बड़े व्यक्तिगत इनाम जिनमें छोटी या हल्की सेवा है, को शामिल नहीं किया है। दूसरी ओर, किसी पदाधिकारी को सेवा के बदले में पारिश्रमिक देने के लिए दिया गया भूमि अनुदान हमेशा दोबारा शुरू किया जा सकता है, यदि वह सेवा करने के लिए पद पर बने रहना बंद कर देता है।

इस मामले में अब प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया जा सकता है। रोमन कैथोलिक मिशन का मानना है। कि ये व्यक्तिगत इनाम हैं और ये धारा 44-बी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस दलील को जिला जज ने स्वीकार कर लिया। उनके अनुसार, इनाम मेला रजिस्टर में नामित व्यक्तियों के पूर्वजों को मंदिर में सेवा करने के दायित्व के अधीन बनाया गया था। इस प्रकार यह माना जाता है कि इनाम किसी कार्यालय, अर्चक या अन्य से जुड़ा नहीं है; न ही उस कार्यालय के लिए आय पारिश्रमिक है। यह आग्रह किया जाता है कि ऐसा इनाम हस्तान्तरणीय है, और यदि सेवा जारी रहती है, तो हस्तान्तरित को वितरित नहीं किया जा सकता है और वह इनाम का आनंद ले सकता है। उच्च न्यायालय ने देवस्थानम के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि इनाम अर्चकों के कार्यालय और इस तरह की सेवा के लिए दिया गया था। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि इनाम कार्यालय से

जुड़ा हुआ है और इस प्रकार हस्तांतरण के लिए अक्षम है और यदि हस्तांतरित किया जाता है तो वह फिर से पुनर्गठन होने के लिए उत्तरदायी है।

यह कौन सा है, इसका निर्णय करने में, कुछ दस्तावेज प्रकाश की बाढ़ ला देते हैं। प्रदर्श ए-3 जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, इस इनाम को देवेयम इनाम कहा जाता है और फिर स्टेलेथर इनाम पोरुपु मन्यम कहा जाता है "मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, थाती देवस्थानम के लिए आयोजित"। भट्टारों के नाम पर इनाम दर्ज किया जाता है। देवदायम शब्द का प्रयोग आमतौर पर राजस्व अभिलेखों में किसी मंदिर से जुड़ी भूमि का वर्णन करने के लिए किया जाता है और शब्दकोशों में इसका अर्थ 'मंदिर के समर्थन के लिए भूमि या भत्ता' है। अभिव्यक्ति स्थानथेर पोरुप्पु मन्यम या संक्षेप में स्थल मन्यम का अर्थ है कम या छोड़े गए किराए पर रखी गई भूमि। पोरुप्पु शब्द का अर्थ किराया छोड़ना भी है। इस प्रकार इस दस्तावेज से पता चलता है कि भट्टारों को ये ज़मीनें मंदिर की सेवा के प्रदर्शन के लिए इनाम में दी गई थीं, लेकिन अनुदान प्राप्तकर्ता के व्यक्तिगत इनाम के रूप में नहीं दी गई थीं। उच्च न्यायालय ने ठीक ही बताया कि उसी दस्तावेज "शन्मुगसुंद्र भट्टर मृत्युंजय भट्टर इनाम" में वर्णन केवल इनामदारों के संदर्भ में इनाम का विवरण था, लेकिन इन परिस्थितियों में इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि इनाम उनका व्यक्तिगत इनाम था।

आगे प्रदर्श ए 11, इनाम मेला रजिस्टर 1863, मूल अनुदान प्राप्तकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं करता है जो कि अनुदान व्यक्तिगत होने पर होता। दो भट्टरों के नाम दर्ज किए गए हैं, लेकिन पगोडा मीनाक्षी सुंदरेश्वरल के अथानिकम के रूप में और इनाम को अर्चाकाल सेवा के लिए देवदायम के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात, मंदिर में पूजा परिचक्रम के लिए और यह कहा गया है कि इनाम आयुक्त ने इनाम की पुष्टि की है।

अब कई मामलों में, न्यायिक समिति द्वारा इनाम जांच को एक मील का पत्थर माना गया है। अरुणाचलम चेट्टी और अन्य बनाम वेंकटचलपति गुरुस्वामीगल⁶ मामले में इनाम मेला रजिस्टर को अत्यधिक महत्व दिया गया था, जिसकी तैयारी को एक महान कार्य के रूप में वर्णित किया गया था। राज्य। नारायण भगवंतराव गोसावी बालाजीवाला बनाम गोपाल विनायक गोसावी⁷ मामले में, इस न्यायालय ने अन्य सबूतों के अभाव में, इनाम आयोग के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि अनुदान एक देवस्थान को दिया गया था और एक देवस्थान इनाम का गठन किया गया था।

श्री रामचन्द्र अय्यर ने प्रयास किया, हमें साबित करें कि प्रिवी काउंसिल के फैसले में अभिव्यक्ति 'राज्य का कार्य' शब्द का दुरुपयोग था और कुछ मामलों का हवाला दिया गया जहां राज्य के अधिनियम पर चर्चा

6- एलआर 46 आईए 204

7- [1960] 1 एससीआर 773

की गई है। हम उनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते। राज्य का कार्य शब्द का अर्थ हमेशा किसी विदेशी के विरुद्ध एक संप्रभु कार्य नहीं होता है जो न तो कानून पर आधारित होता है और न ही ऐसा होने का दिखावा करता है। इस शब्द का अर्थ उससे कहीं अधिक है क्योंकि इसके कई अर्थ हैं। सौराष्ट्र राज्य बनाम मेमन हाजी इस्माइल हाजी⁸ में इस शब्द के अन्य अर्थ दिये गये हैं। यहां यह उस अधिनियम को इंगित करता है जिसके संबंध में एक आधिकारिक घोषणा थी। इनाम मेला रजिस्टर में एक आधिकारिक घोषणा शामिल की गई जो विस्तृत पूछताछ का परिणाम थी। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने या घोषित करने से पहले प्रत्येक इनाम के संबंध में एकत्र किए गए सभी सबूतों को सावधानीपूर्वक जांचा और विचार किया गया था। इसके विपरीत सकारात्मक और उचित साक्ष्य के अभाव में ऐसी घोषणा का सर्वोच्च महत्व होना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण है कि रोमन कैथोलिक मिशन ने, जैसा कि मूल रूप से दायर किया गया था, याचिका में कहा था कि अर्चक के कार्यालय को विवाद में भूमि की आय और अन्य स्रोतों की आय से पारिश्रमिक दिया गया था। हालाँकि, जब निर्णय सब नोम होता है, मद्रास उच्च न्यायालय के पीवी भीमेना राव बनाम येला रेड्डी की रिपोर्ट (1954) 1 एमएलजे 384 सुचित होता है तो उसमें एक संशोधन द्वारा दलील दी गई थी कि इनाम

8- [1960] 1 एससीआर 537, 543

एक व्यक्तिगत इनाम था। जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपील के तहत फैसले में बताया है, भट्टार और रोमन कैथोलिक मिशन के बीच मुकदमा चल रहा था और जिन साक्ष्यों पर हमने चर्चा की है, वे मिशन को तब ज्ञात रहे होंगे जब मूल याचिका दायर की गई थी। तथ्य यह है कि उनकी दलील यह थी कि यह अर्चकों के कार्यालय के पारिश्रमिक के लिए एक इनाम था, इन दस्तावेजों के सही अध्ययन का प्रतिनिधित्व करता है। इनाम मेला रजिस्टर इनाम को देवदायम के रूप में बताता है और इसे स्थायी के रूप में पढ़ता है। यदि इनाम व्यक्तिगत रूप से किसी ब्राह्मण का होता तो इसे 'ब्रह्मदायम' और 'वंशानुगत' के रूप में दिखाया जाता।

अंततः प्रदर्श ए-10, जो मुथुमीनाक्षीअम्मल का बयान है जो 1863 में इनाम का आनंद ले रहा था, इसमें कहा गया है "

"इनाम कैसे प्राप्त किया गया इसका विवरण और कर्मों का सार।

नेन्जाकनि 39

हमारे पूर्ववर्तियों के समय में मीनाक्षी सुंदरेश्वरल के उक्त स्थानथार इनाम और जैसे हमारे पूर्ववर्तियों ने आनंद लिया, हम भी उपरोक्त मणिबम में, मैं मुथु मीनाक्षी अम्मल आधा हिस्सा, मैं पोन्नम्मल 1/4 हिस्सा, हम कल्याण बत्तर और भिन्ना सुब्बा बत्तर 1/8 वां हिस्सा और हम विल्लू बत्तर उर्फ शुनमुगा सुंदरा बत्तर 1/8 वां हिस्सा, हम उपरोक्त मनिबा भूमि का

उपरोक्त तरीके से आनंद ले रहे हैं और हम अपने आनुपातिक हिस्से के अनुसार उसके संबंध में पोरुप्पु मान्यम का भुगतान कर रहे हैं और हम भी हैं जैसा कि हमारे पूर्ववर्तियों ने आनंद लिया था, उक्त मणिबम का आनंद लेते रहे। हम उपरोक्त मंदिर में अर्चकम (पूजा) कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं।"

इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इनाम को हमेशा मंदिर की अर्चक सेवा के लिए पारिश्रमिक माना जाता था और इसके हस्तांतरण पर यह धारा 44-बी के तहत फिर से शुरू करने के लिए उत्तरदायी है। धारा 44 बी को निगमित करने से पहले भी राजस्व बोर्ड के नियम 54(1) के स्थायी आदेश के तहत, के ऐसे इनाम को सरकार द्वारा फिर से शुरू किया जा सकता था (देखें अंजनयालु बनाम श्री वेणुगोपाला राइस मिल लिमिटेड ⁹। श्री रामचन्द्र अय्यर यहां तक इस मामले की सत्यता पर सवाल उठाने का भी प्रयास किया गया, जिसका लगातार पालन किया गया है। विद्वान जिला न्यायाधीश, मदुरै का निष्कर्ष, कि यह एक व्यक्ति का व्यक्तिगत इनाम था, गलत था और उच्च न्यायालय ने इसे उलटने में सही किया था

श्री रामचन्द्र अय्यर आगे तर्क देते हैं कि जब विधायिका ने इसे अधिनियमित करना चाहा तब धारा 44-बी अमान्य थी, और इसलिए, इसके तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह तर्क बहुआयामी है और

9- आईएलआर 45 मैड 624 पर 620 (एफडी) 10 सुपर.सीएल/66-6

अक्सर अस्पष्ट होता है। संक्षेप में कहा गया, तर्क यह है: इनाम की पुष्टि 25 सितंबर, 1863 को इनाम आयुक्त द्वारा शीर्षक विलेख 1354 के तहत की गई थी। 'अधिकारों का अलगाव, चाहे वे कुछ भी हों, उस तारीख से पहले थे। इनाम आयोग से पहले कोई निषेध नहीं था और पुष्टि पूर्व अलगाव को प्रभावित नहीं कर सकती थी। चूंकि इनाम कार्यों को ब्रिटिश संसद का अधिनियम (32 और 33 विक्ट. सी. 29) द्वारा मान्य किया गया था। इनाम रियायत को जब्त करने या इसे फिर से शुरू करने का अधिकार क्राउन द्वारा प्रयोग किया जा सकता था क्योंकि इनाम भारत राज्य सचिव व इनाम धारक के बीच एक अनुबंध बन गया था। धारा 44-बी को शून्य कहा जाता है क्योंकि यह इस स्थिति के साथ विरोधाभासी है और राजस्व अधिकारियों को बहाली का आदेश देने में सक्षम बनाती है। अपने व्यक्तिगत फैसले के अभ्यास में गवर्नर जनरल या गवर्नर के आदेश के बिना बहाली या जब्ती को अप्रभावी कहा गया था और इसलिए भी कि इनाम को फिर से शुरू करने का अधिकार निर्धारण द्वारा समाप्त हो गया था। पुनः आरंभ को जब्ती के रूप में वर्णित किया गया था और कहा गया था कि यह धारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 299 और संविधान के अनुच्छेद 31 और 296 के तहत शून्य था। मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम (1951 का XIX) जो धारा 35 द्वारा 44-बी को अधिनियमित करता है, को आगे शून्य कहा गया क्योंकि, यह कहा गया था, यह केवल हिंदू धार्मिक संस्थानों की रक्षा करना चाहता है, न कि अन्य धर्मों से

संबंधित संस्थानों की। प्रांतीय विधायिका की 1934 व 1946 में 44-बी अधिनियम बनाने की शक्ति को भी क्रमशः भारत सरकार अधिनियम 1915 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत चुनौती दी गई थी।

जिला न्यायाधीश ने अंतिम तर्क को छोड़कर इनमें से किसी भी तर्क पर विचार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देवस्थानम और राज्य सरकार के खिलाफ बहाली के मुद्दे का फैसला किया था। जिला न्यायाधीश ने फैसला किया कि यह धारा प्रांतीय विधायिका द्वारा वैध रूप से अधिनियमित की गई थी। हालाँकि, जिला न्यायाधीश ने फैसले में उन सभी तर्कों का उल्लेख किया जो उनके सामने उठाए गए थे और वे तर्क थे जो हमने ऊपर निर्धारित किए हैं। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय में इनमें से अधिकांश तर्क आगे नहीं बढ़ाए गए हैं क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय उनके बारे में मौन है। हमने श्री रामचन्द्र अय्यर को सूचित किया कि हम किसी भी ऐसे तर्क को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे जिस पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को आमंत्रित नहीं किया गया हो। उच्च न्यायालय में धारा 44 बी की वैधता मद्रास अधिनियम और 1951 के अधिनियम की धारा 35 पर प्रांतीय विधायिका की शक्तियों के दृष्टिकोण से और दोनों के संबंध में संविधान के दृष्टिकोण से विचार किया गया था। हम इन तर्कों पर मुख्य रूप से उन्हीं दो दृष्टिकोणों से विचार करेंगे।

भारत सरकार अधिनियम, 1915 के तहत प्रांतीय विधायिकाओं की शक्तियां भारत सरकार अधिनियम की धारा 45-ए और 129-ए के तहत काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए हस्तांतरण नियमों के तहत निर्धारित की गई थीं। इन नियमों के द्वारा गवर्नरों के प्रांतों की स्थानीय सरकारों और स्थानीय विधायिकाओं के कार्यों को काउंसिल में गवर्नर जनरल और भारतीय विधानमंडल के कार्यों से अलग करने के उद्देश्य से विषयों का वर्गीकरण किया गया था। हस्तांतरण नियम दो सूचियों में वर्गीकृत विषयों को निर्धारित करते हैं और अनुसूची I के भाग II में निर्धारित प्रांतीय विषयों की सूची में किसी भी मामले को किसी भी केंद्रीय विषय से बाहर रखा गया था। इन नियमों के नियम 4 के तहत, यदि कोई संदेह उठता है कि कोई विशेष मामला प्रांतीय विषय से संबंधित है या नहीं, तो काउंसिल में गवर्नर जनरल को यह तय करना था कि मामला संबंधित है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम था।

समय की इस दूरी पर, उचित जांच के बिना किसी न्यायालय के लिए यह तय करना कुछ हद तक अयोग्य है कि प्रांतीय विधायिका की शक्तियां धारा 44-बी के निर्माण तक विस्तारित थीं या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, यह समान प्रश्न उठाया गया होगा और काउंसिल में गवर्नर जनरल का निर्णय प्राप्त किया गया होगा। मामला यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि किसी ने भी इस धारा को चुनौती नहीं दी है, हालांकि

उस धारा के तहत कई इनाम फिर से शुरू किए गए थे। हालाँकि, इस मामले पर सैद्धांतिक रूप से विचार करने पर हमें प्रांतीय विधायिका की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं लगता है। जैसा कि जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने ठीक ही बताया है, प्रांतीय विधायिकाओं की शक्तियाँ भूमि कार्यकाल, भूमि राजस्व प्रशासन और धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती तक विस्तारित थीं। इन कई शक्तियों के संयोजन से स्पष्ट रूप से इसके लिए पर्याप्त गुंजाइश मिलनी चाहिए, सामान्य रूप से इनाम और विशेष रूप से धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती से जुड़े इनाम के विषय पर सबसे व्यापक कानून लेना। इस प्रकार धारा 44-बी पूरी तरह से प्रांतीय विधायिका की क्षमता के अंतर्गत थी।

अगला प्रश्न जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार किया कि क्या किसी हिंदू मंदिर का इनाम फिर से शुरू करना और उसे वापस देना संविधान का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. यह स्पष्ट है कि इनाम के हस्तांतरण से मंदिर को लाभ से वंचित कर दिया गया था और हस्तांतरणकर्ता को उस लाभ को रखने का कोई अधिकार नहीं था। जो किया गया वह मंदिर को वह सब वापस दिलाने के लिए था जो उसने खोया था और इससे किसी सांप्रदायिक धार्मिक संस्था को लाभ नहीं हो रहा था।

एक बार जब हम मान लेते हैं कि प्रांतीय विधायिका के पास विवादित धारा को अधिनियमित करने की क्षमता है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह धारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 292 द्वारा कायम रहेगी। वास्तव में, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधायिका की शक्तियाँ विधायिका की तुलना में जिसने इस धारा को अधिनियमित किया ज़रा भी कम नहीं थीं। 1946 में धारा के किसी भी संशोधन को 1935 के अधिनियम के तहत भी स्पष्ट अधिकार होगा। और यही संविधान तथा मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ अधिनियम, 1951 के बारे में कहा जा सकता है।

यह सिद्धांत कि भारत के राज्य सचिव और इनाम-धारकों के बीच अनुबंध 32 और 33 विक्ट सी. 29 के पारित होने के बाद अस्तित्व में आया। और यह कि इसने मामले को प्रांतीय विधानमंडलों को हस्तांतरण नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर कर दिया, यह भी उतना ही गलत है। वास्तव में यह हुआ था। 1858 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, जो कि क्राउन के भरोसे क्षेत्रों पर थी, समाप्त हो गई, ब्रिटिश संसद ने " भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम " पारित किया। हमें इसके प्रावधानों से कोई सरोकार नहीं है। एक साल बाद 1858 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक और अधिनियम पारित किया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि 1858 के अधिनियम के तहत भारत में अचल

संपत्ति के निपटान के उद्देश्य से महामहिम में निहित किसी भी विलेख, अनुबंध या अन्य दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए भारत के राज्य सचिव की ओर से या काउंसिल में गवर्नर जनरल या फोर्ट सेंट जॉर्ज या काउंसिल में बॉम्बे के गवर्नर के आदेश से व्यक्त किया जाना चाहिए। यद्यपि यह कानून मौजूद था, इनाम आयुक्त द्वारा जारी किए गए शीर्षक विलेखों को काउंसिल के राज्यपाल के आदेश द्वारा परिषद में निष्पादित करने के लिए व्यक्त नहीं किया गया था और भारत के लिए राज्य के सचिव की ओर से बजाय परिषद में राज्यपाल की ओर से निष्पादित किया गया था। इससे उनके अंतर्गत बनाए गए शीर्षक की वैधता के बारे में संदेह पैदा हो गया। 32 एवं 33 विक्ट सी 29 के अधिनियमन द्वारा इनाम भूमि के स्वामित्व विलेखों को मान्य किया गया। उन्हें पढ़ा जाना था और उनका प्रभाव वैसा ही होना था जैसे कि उन्हें काउंसिल में गवर्नर के आदेश से और काउंसिल में भारत के राज्य सचिव की ओर से निष्पादित किया गया हो। इस प्रकार नए स्वामित्व विलेखों को दोबारा जारी किए बिना अनेक अनुदानों की खामियां दूर कर दी गईं।

इस कानून ने कोई अनुबंध नहीं बनाया। इसने केवल पुराने स्वामित्व विलेखों को मान्य किया और इससे अधिक नहीं। उन अनुदानों को पढ़ने के लिए जिनके द्वारा इनाम बनाए गए थे, एक अनुबंध जो क्राउन द्वारा फिर से शुरू करने के अलावा उल्लंघन योग्य था, ब्रिटिश संसद के अधिनियमों में

कुछ ऐसा पढ़ने के समान है जो वहां नहीं है। किसी भी अन्य अनुदान की तरह जो अपनी शर्तों के उल्लंघन पर फिर से शुरू किया जा सकता है, ये इनाम उनके नियमों और शर्तों के अनुसार फिर से शुरू किए जा सकते हैं। इनाम शीर्षक-विलेख या इन कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो प्रांतीय विधायिका को अपनी निस्संदेह शक्तियों के तहत अधिनियम बनाने से रोकता हो या कलेक्टर को धारा द्वारा दी गई शक्ति के तहत इसकी शर्तों के उल्लंघन पर इनाम को फिर से शुरू करने से रोकता हो।

धारा 44-बी की वैधता के विषय पर अन्य तर्क हमें निरोध नहीं करते हैं। वे इसकी शर्तों के उल्लंघन के लिए इनाम को फिर से शुरू करने और ज़ब्त करने के बीच के अंतर को मिटाने पर आगे बढ़ते हैं, जो कि भूमि के मालिक या मालिक के किसी अवैध कार्य या लापरवाही के लिए कानून द्वारा संलग्न एक प्रकार की सजा है। यहां हमारा संबंध ज़ब्त करने से नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा दी गई रियायत को फिर से शुरू करने से है, जो किसी अजनबी को रियायत दिए जाने के कारण होती है। ज़बती पर आधारित कोई भी तर्क पूरी तरह से अनुचित है। इसी प्रकार, हमारे द्वारा पहले उल्लिखित संविधान के अनुच्छेदों पर निर्भरता द्वारा पर्याप्त रूप से संकेतित वास्तविक रिक्तता या संपत्ति से वंचित करने पर आधारित तर्क आंशिक रूप से मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वे अप्रासंगिक हैं और मुख्य रूप से क्योंकि ऐसा कोई तर्क उच्च न्यायालय में पेश नहीं किया गया है

हम तदनुसार उस तर्क को अस्वीकार करते हैं जो धारा 44-बी या इसके तहत पुनः आरंभ अमान्य थे।

केवल प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न ही शेष रह जाता है। बोड्डापल्ली जगन्नाधम और अन्य बनाम राज्य सचिव ¹⁰ यह माना गया कि किसी भी कानून द्वारा कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है जिसके भीतर अकेले सरकार को सार्वजनिक राजस्व के साथ मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी भूमि पर मूल्यांकन लगाने के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस मामले का पालन सुब्रमण्यम चेट्टियार बनाम राज्य सचिव¹¹ में किया गया था। चूँकि बहाली केवल मेल्वारम की थी, अतः ये निर्णय लागू होते हैं। श्री रामचन्द्र अय्यर ने स्वीकार किया कि उनके पास इसके विपरीत कोई प्राधिकार नहीं था। इस बिंदु में कोई बल नहीं है। यह अपील (1964 की सिविल अपील 389) भी असफल होनी चाहिए।

तदनुसार दोनों अपीलें लागत सहित खारिज की जाती हैं । लागत निर्धारित करने का अधिकार होगा.

अपीलें खारिज.

10- आईएलआर 27 मैड 16.

11- 28 एमएलजे 392.

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री अभिषेक कोडप (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)